AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के साथ स्थिति और चुनौतियाँ

Rafiq Ali[1] and Dr. Suresh Kumar Jat[2]

[1]Research Scholar, Mansarovar Global Uninversity, Sehore (M.P)

[2]Research Supervisor, Mansarovar Global Uninversity, Sehore (M.P)

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/ OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

2009 में सभी बच्चों के लिए शिक्षा का विशेषाधिकार अधिनियम एक वर्तमान प्राथमिक विद्यालय मैं सुधार हुआ है। यह अध्ययन बामोर नगरपालिका क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की समस्याओं की जांच करता है। अनुच्छेद 21 ए को 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक नए मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। 26 अगस्त, 2009 को, राज्य सभा और लोकसभा दोनों ने सरकार के अनुमोदन से अधिनियम को मंजूरी दी।

2009 का आरटीई अधिनियम घोषित होने के बाद 1 अप्रैल 2010 को स्थापित किया गया था। इस जांच में एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। बामोर क्षेत्रीय निगम प्राथमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले जितने आवश्यक थे। साथ ही सेवाकालीन शिक्षण सहायकों से जानकारी एकत्र की गई थी।

आरटीई अधिनियम के संबंध में शिक्षकों की धारणाओं, समस्याओं और समाधानों का अध्ययन ओपन-एंडेड प्रश्नों के साथ एक ओपन-एंडेड सर्वेक्षण का उपयोग करके किया गया था। अध्ययन

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

के निष्कर्षों ने नीतियों के हस्तक्षेपों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाया और उन्हें आम तौर पर जमीन पर कैसे पहचाना और निष्पादित किया जाता है।

कीवर्ड्स:- *प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, स्थिति और चुनौतियाँ।*

1. प्रस्तावना

आरटीई अधिनियम छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार ने 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की स्थापना की। अनुच्छेद 21 पारित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सभी बच्चों की शिक्षा की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 2010 से, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत में कानूनी व्यवस्था लागू हो गई। कानून के प्रभावी होने के बाद, भारत उन 135 देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है।

आरटीई अधिनियम, 2009 शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है और यह स्कूली शिक्षा पर पहला केंद्रीय कानून है। 2010 में, देश ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया जब अनुच्छेद 21-ए और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू हुआ। यह हमारी संसद का 'ऐतिहासिक' विधान है। इस संशोधन से पहले, "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों" की सूची के अनुच्छेद 45 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 45 कहता है कि वह राज्य सभी बच्चों की 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

भारतीय संसद ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 पारित किया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक स्थानीय स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में स्नातक होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यह 6 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों की सूची है जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। छह वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक बच्चा जिसे अभी तक किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है या जिसने किसी भी कारण से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, वह अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में रखे जाने का हकदार है।

1.1 प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति:

भारत की शिक्षा प्रणाली का विकास किस पर अधिक ध्यान देने से प्रेरित है? बुनियादी प्रारंभिक शिक्षा। भारत की शिक्षा प्रणाली प्रमुख उपलब्धियों में से एक आजादी के बाद से देश की साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि 1951 में 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गया।

1.2 प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन:

सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं (2001) और मध्याह्न भोजन योजना (1995) को इसका श्रेय दिया जा सकता है | पिछले एक दशक में भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के कारण 2,00,000 से अधिक नए स्कूलों का गठन हुआ है 21 मिलियन से अधिक बच्चों का अतिरिक्त नामांकन। उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देखा गया, जो 1950-51 से 2005-06 लगभग 20 गुना बढ़े हैं

2. अध्ययन का उद्देश्य

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

1. यह शोध आरटीई अधिनियम 2009 की आवश्यक आवश्यकताओं और तत्वों को समझने के लिए आवश्यक है।
2. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आरटीई अधिनियम को लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना।
3. आरटीई अधिनियम के आवेदन में अंतर को पाटने के तरीकों की तलाश करना।

3. संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

अनुसंधान उस ज्ञान का नेतृत्व करता है जो अतीत में निरंतर मानव उपलब्धि के परिणामस्वरूप एकत्र किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तावित अध्ययन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित समस्याओं पर जो कार्य पहले ही किया जा चुका है, उसे पृथक करके कभी नहीं किया जा सकता।

कृष्णशास्त्री वी.एन.वी. (1970) ने "प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बीच" पर एक अध्ययन किया कोयस" और देखा कि पारंपरिक गतिविधि, प्रवास, कक्षा को दोहराना या विफलता आदि, हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य बाधाएं।

दांडेकर (1955), और दास आर.सी. (1970) ने "अपव्यय की समस्याएँ और" की जाँच की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर ठहराव"।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

नाइक जे.पी. (1975) ने अपनी पुस्तक "एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया - ए प्रॉमिस टू कीप" में समझाया प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के पारंपरिक मॉडल को कैसे प्रभावित करने के लिए मौलिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए 1986 तक सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा।

✓ *आरटीई अधिनियम 2009 की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने के लिए*

1. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य के लिए 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
2. यह अधिनियम एक बच्चे को स्कूल जाने और प्रवेश लेने का अधिकार देता है, भले ही उन्होंने पहले कोई औपचारिक शिक्षा न ली हो।
3. यह अधिनियम एक बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के किसी भी समय स्कूल जाने और प्रवेश लेने का अधिकार देता है।
4. अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह आयु प्रमाण का कोई दस्तावेज प्रदान नहीं कर सकता है।
5. यह अधिनियम निजी शिक्षा संस्थानों को 2011 में कक्षा 1 से शुरू होने वाली कक्षाओं के 25% को वंचित छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करने का भी निर्देश देता है।
6. अधिनियम के चौथे अध्याय का खंड 28 शिक्षकों को किसी भी निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न होने से रोकता है।
7. अधिनियम के अध्याय iv का खंड 17 (1) स्कूलों को कोई भी शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देने से रोकता है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

8. यह अधिनियम प्रत्येक स्कूल को पर्याप्त शिक्षक, खेल का मैदान और बुनियादी ढांचे जैसी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्देश देता है।
9. अधिनियम में पड़ोस के स्कूलों की एक नई अवधारणा शामिल है। 10. इस अधिनियम में कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए भी प्रावधान है जो गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।

4. शिक्षा का अधिकार

अधिनियम को लागू करने में चुनौतियां भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 2009 को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पारित किया गया था। अनुच्छेद 21 (ए) के तहत 6-14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने में कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया गया है जिनकी चर्चा नीचे की गई है-

- **ज्ञान की कमी:** अधिकांश शिक्षक आरटीई अधिनियम के बारे में स्पष्ट नहीं हैं और वे इसे अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर लागू कर रहे थे। शिक्षकों के लिए आरटीई अधिनियम के बारे में पूरी समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं को कम से कम किया जा सके। साथ ही, अधिनियम के बारे में ज्ञान उन्हें इसे समझने और अंततः स्थिति की आवश्यकता के अनुसार इसे लागू करने में मदद करेगा।
- **प्रशिक्षण और पर्याप्त जानकारी का अभाव:** अधिकांश शिक्षकों ने स्कूली शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आरटीई का स्वागत किया। अधिकांश शिक्षकों ने उत्तर दिया कि

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

अधिनियम सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण की कमी और पर्याप्त जानकारी शिक्षकों द्वारा आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां हैं।

- **स्पष्टता की कमी:** आज लगभग 50% शिक्षकों ने जवाब दिया कि आरटीई अधिनियम अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में कोई स्पष्टता दिए बिना स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ाता है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता करता है, जो संदिग्ध कार्यान्वयन की ओर ले जाता है। कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश उचित नहीं हैं और छात्रों के प्रतिधारण की उपेक्षा की जाती है।
- **उच्च छात्र शिक्षक अनुपात:** शिक्षकों की एक अच्छी संख्या ने जवाब दिया कि स्कूलों में उच्च छात्र शिक्षक अनुपात था। इसलिए यह शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने से भी रोकता है। और यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रभावों को भी बताता है। कुछ शिक्षकों ने अधिनियम में स्पष्टता का अभाव पाया। शिक्षकों ने जवाब दिया कि अधिकारियों को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ा सकें।
- **संसाधनों की कमी:** संसाधनों की भी कमी है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने में भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दस प्रतिशत (10%) शिक्षकों ने मांग की कि भौतिक बुनियादी ढांचे, मौद्रिक और मानव संसाधन आदि सहित संसाधनों को भी बढ़ाया जाए।

5. निष्कर्ष

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन को पहले के स्पष्टीकरण के आधार पर लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि केवल कुछ प्रतिशत छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षकों को अधिनियम के बारे में पता है। यद्यपि आरटीई अधिनियम ने स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि की है, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना अभी भी एक प्राथमिकता है।

शिक्षक, जो शिक्षा सेवाओं के प्रदाता हैं, को आरटीई अधिनियम को लागू करना आवश्यक है, जिसके बारे में उनके पास कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था। आरटीई एक्ट के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है।

इसका अधिनियम के कार्यान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान से यह पाया गया है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है और उन्हें आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अपनी कक्षाओं को व्यवस्थित करने के तरीकों पर नियमित कौशल प्राप्त होता है।

स्कूलों में नामांकन बढ़ने के साथ, शिक्षकों, प्रबंध समितियों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है और स्कूलों के पास सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन हैं। आरटीई अधिनियम स्पष्ट रूप से सरकार की दृढ़ता बनाता है। भारत के हर बच्चे की शिक्षा प्रदान करने के लिए। अधिनियम के विभिन्न प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि देश ने राष्ट्र परिवर्तन के लिए शिक्षा को अपने एजेंडे में रखा है। इसने बच्चों के लिए मूल्यवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से संरक्षित वातावरण तैयार किया है जो भविष्य के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य कर सकता है। यह अधिनियम निश्चित रूप से साक्षरता दर में सुधार लाने और बच्चों को दुनिया में उनके सही स्थान की गारंटी देने पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करेगा।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

"संदर्भ"

1. डी हान, अर्जुन (2005) "सोशल पॉलिसी: टुवर्ड्स इनक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस", यूनिवर्सिटी ऑफ गेलफ एंड डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूके।
2. विश्व बैंक सम्मेलन में पेपर 'सामाजिक नीति के नए मोर्चे: एक वैश्वीकरण दुनिया में विकास': 12-15 दिसंबर, 2005।
3. रामचंद्रन, विमला (सं.) (2002) प्राथमिक शिक्षा यूरोपीय आयोग, नई दिल्ली में लिंग और सामाजिक समानता।
4. रामचंद्रन, विमला (सं.) (2004) प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक समानता: पहुंच के पदानुक्रम, सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. मेहरोत्रा, संतोष (2006) भारत में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थशास्त्र: सार्वजनिक वित्त की चुनौती, निजी प्रावधान और घरेलू लागत, सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. मेहरोत्रा, संतोष (2006) "भारत में जाति और मानव विकास: एक उत्तर दक्षिण विभाजन की व्याख्या", "सामाजिक कार्य: दक्षिण एशिया में एमडीजी प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक कवरेज और परिवर्तन की ओर", काठमांडू, नेपाल पर यूनिसेफ-यूएनआरआईएसडी कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। , 24-26 मई, 2006।
7. प्रोब टीम (1999) इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
8. मोड रिसर्च (1995) एटिट्यूड स्टडी ऑन एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया - एक समेकित रिपोर्ट। यूनिसेफ, नई दिल्ली द्वारा कमीशन।

ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

9. शिक्षा विभाग (2006) सर्व शिक्षा अभियान: चौथा संयुक्त समीक्षा मिशन। एड मेमोयर, नई दिल्ली।

10.शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति, ग्रामीण (एएसईआर) रिपोर्ट, प्रथम, असर केंद्र, नई दिल्ली (2013)

11.डे ला वेगा, सी. 1994। समान शिक्षा का अधिकार: प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानूनी अधिकारों के लिए केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत। हार्वर्ड ब्लैक लेटर लॉ जर्नल, 11:37-60।

12.हॉजसन, डी। 1998। शिक्षा का मानव अधिकार। एशगेट: डार्टमाउथ पब्लिशर्स

13.नोवाक, एम। 1995। शिक्षा का अधिकार। ईद में, ए. और क्रूस, के. (सं.). आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। बोस्टन: क्लूवर अकादमिक प्रकाशक: 189-211।

14.रिंज, सीए 1981. बच्चों के अधिकार: एक दार्शनिक अध्ययन। लंदन: रूटलेज/कोगन. अराजर्वी। पी। 1992। एड, ए।, अल्फ्रेडसन जी।, मेलेंडर, जी।, रेहोफ, एल।, ए। और रोजास, ए में अनुच्छेद 26। (सं.). मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा: एक टिप्पणी। लंदन: स्कैंडिनेवियाई यूनिवर्सिटी प्रेस:405-428।

15.डेट्रिक, एस। 1999। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर टिप्पणी। द हेग: मार्टिनस निजॉफ पब्लिशर्स।

AIRO JOURNALS

Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN:2320-3714
Volume 4 Issue 3
December 2022
Impact Factor: 6.3
Subject: Humanities

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

Rafiq Ali
Dr. Suresh Kumar Jat